भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति

09 जनवरी, 2015

dk;yk etnjk d lEFku e

सन् 1977 के बाद पहली बार सबसे बड़ी व दो दिनी हड़ताल को अंजाम देने वाले कोयला खदानों के लाखों मजदूरों का भाकपा (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी हार्दिक व क्रांतिकारी अभिनंदन करती है और उन्हें लाल सलाम पेश करती है।

देश के कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत से ज्यादा एकाधिकार प्राप्त कोल इंडिया में निजी क्षेत्र के प्रवेश के खिलाफ पांच मजदूर संगठनों के द्वारा आयोजित दो दिनी हड़ताल सरकारों के निजीकरण नीतियों की ओर देश को ध्यान खीचनें में सफल रही। केंद्र सरकार ने मजदूरों की संगठित शक्ति के दबाव में आकर अस्थायी रूप से यह हामी भरी कि वह कोल इंडिया का निजीकरण नहीं करेगी। लेकिन इस हामी पर यकीन करना नादानी होगी। केंद्र में सत्तारूढ़ होते ही भाजपा की मोदी सरकार ने 'मेक इन इंडिया', 'मेड इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' के नारों को बुलंद रखी हुई है जिनके तहत विदेशी पूंजीपतियों को देश की सार्वजनिक संपति व संसाधनों को लूटने का खुला निमंत्रण दिया गया है। एक ओर स्वदेशी, राष्ट्रीयता, देशभक्ति का रट लगाते हुए ही दूसरी ओर ये नारे दिये जा रहे हैं। रेल्व, प्रतिरक्षा, बीमा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 49 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। यहां पर यह उल्लेख करना लाजिमी होगा कि 2001 में भाजपा की ही वाजपेयी सरकार ने एफडीआई को 26 प्रतिशत बढ़ाया था। टेक्सटाइल, टेलिकॉम व खुदरा व्यापार में भी एफडीआई की अनुमति दी गयी। कोल इंडिया के कोल आबंटनों के लाइसेंसों को पिछले साल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रद्व किये जाने के बाद सरकार ने निजी कंपनियों को नीलामी में भाग लेने की अनुमति देने का निर्णय लिया। इसे कोल इंडिया के निजीकरण की पहली सीढ़ी मानी जानी चाहिए। हालांकि ऊर्जा मंत्री पीयुष गोयल ने श्रमिक संगठनों से बातचीत में कोल इंडिया के निजीकरण न करने की हामी भरी थी लेकिन केंद्र सरकार की जनविरोधी, देशविरोधी नीतियों के अमल में तेजी को देखते हुए गोयल की हामी पर कतई विश्वास नहीं किया जा सकता है। हमारी पार्टी कोल इंडिया के मजदूरों से हर पल सजग, सतर्क व सावधान रहने की अपील करती है। यह सरकार कभी भी कोल इंडिया का निजीकरण कर सकती है। नवरत्न व महारत्न कहलाने वाले देश के महत्वपूर्ण पीएसयू में विनिवेशीकरण के द्वारा वित्तीय घाटे को कम करने, विदेशी कर्जा व ब्याज चुकाने पूंजी हासिल करना उसकी घोषित नीति है। पूर्व में नवरत्नों में से एक बाल्को के विनिवेशीकरण के नाम पर माइनपाट बाक्साइट खदान सहित 5000 करोड़ रु की संपति, एवं 300 करोड़ के बैंक रिजर्वों के आधे हिस्से को मात्र 550 करोड़ रुपयों में स्टरलाइट के अनिल अग्रवाल को सौंपा गया था। आज बाल्को मजदूरों का हालत सबके सामने है। 'मेक इन इंडिया', 'मेड इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया', 'स्किल डेवलपमेंट' आदि नारे देशी, विदेशी पूंजीपतियों का 'लूट इन इंडिया' आव्हान के सिवाय और कुछ नहीं है। देश को धर्मान्मादी हिन्दु राष्ट बनाने के एजेण्डे पर एक तरफ जहरीली भारत का निर्माण करते हुए दूसरी ओर 'स्वच्छ भारत' का नारा व योजना असल में जनता की मूलभूत समस्याओं से उनका ध्यान भटकाने की साजिश है। जनविरोधी, देश विरोधी, नीतियों पर अमल करने वाले दलाल, भ्रष्ट नेताओं एवं देशी–विदेशी पूंजीपतियों व जमींदारों के सफाये से ही स्वच्छ भारत का निर्माण होगा जो कि क्रांतिकारी जनयुद्ध से ही संभव है।

हम इस संदर्भ में कोल इंडिया के मजदूरों को चेताना चाहते हैं कि वे देश के जमींदारों व बड़े दलाल औद्योगिक घरानों का प्रति निधित्व करने वाली, साम्राज्यवादीपरास्त सरलीकरण, निजीकरण व भूमंडलीकरण की नीतियों पर अमल करने वाली संसदीय पार्टियों – भाजपा व कांग्रेस से संबंद्ध भारतीय मजदूर संघ, आईएनटीयूसी सहित संशोधनवादी सीपीआई व नव संशोधनवादी सीपीआईएम से संबंद्ध एआईटीयूसी एवं सीआईटीयू पर हर पल अपनी पैनी नजर गढ़ाये रखें।

लंबे संघर्षों व महान कुरबानियों के बलबूते मजदूर वर्ग के द्वारा हासिल उपलब्धियों को छीनते हुए श्रम कानूनों में देशी, विदेशी पूंजीपतिपरास्त व मजदूर विरोधी संशोधन किये जा रहे हैं। श्रम कानूनों में ढ़िलाई देने वाले इन तमाम संशोधनों, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एफडीआई के प्रवेश, सार्वजनिक क्षंत्र के उद्योगों के विनिवेशीकरण के खिलाफ देशव्यापी अनिश्चिकालीन हड़ताल के लिए तैयारी करने हम कोयला मजदूरों सहित पीएसयू के तमाम मजदूरों का आव्हान करते हैं। देशव्यापी संगठित, व्यापक व जूझारू मजदूर आन्दोलन का निर्माण आज का ऐतिहासिक कर्तव्य है।

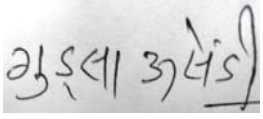

(गुड्सा उसेण्डी)
प्रवक्ता,
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी,
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)